

बजट अनुमान 2021-22 में योजनावार प्रावधान

(आंकड़े हजार रूपयों में)

योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान
573	उच्च न्यायालय (भारत)	82,22,10
1912	दण्ड न्यायालय	40,00
2407	निर्वाचन	36,00
2409	निर्वाचन अधिकारी	21,42,20
2410	निर्वाह पत्र तामिल स्थापना	21,92,10
2449	न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	14,70,00
2450	न्याय प्रशासन	73,63,50
2918	बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता	1,50,00
3255	विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	23,37,90
3307	मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	30,41,44
3428	महाधिवक्ता	11,53,00
3572	मुफस्सिल स्थापना	10,25,80
4006	राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	16,00,30
4311	संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	22,00,30
4497	सामान्य स्थापना	243,89,90
5136	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	1,40,00
5171	विशेष न्यायालयों की स्थापना	7,28,30
5416	परिवार न्यायालय की स्थापना	33,88,30
5421	छत्तीसगढ़, राज्य न्यायिक अकादमी	10,92,70
5464	हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	6,01,00
5640	उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	25,90,00
6222	न्याय प्रशासन के आवासगृह का निर्माण	77,66,00
6356	फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो	9,20,00
7256	न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	5,17,71
7502	सी.बी.आई. न्यायालय की स्थापना	96,25
7798	कॉमर्शियल कोर्ट	1,89,66
7982	राज्य अधिवक्ता संस्थान (लॉयर्स अकादमी)	10,00
8998	भारतीय विधि संस्थान	10,00
9056	माध्यस्थम अधिकरण	2,36,55
9057	विधि एवं विधायी कार्य	9,97,40
9503	मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	2,50,00

बजट अनुमान 2021-22 में योजनावार प्रावधान

(आंकड़े हजार रूपयों में)

योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान
	योग	768,98,41